



CW

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94]

नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, मई 21, 1992/वैशाख 31, 1914

No. 94]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 21, 1992/VAISAKHA 31, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकालन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वस्त्र नियालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 1992

विषय:— केसेक्टर वर्ष 1992-93 के लिए उन देशों को परिवागो तथा
नियन्त्रित के सम्बन्ध में ओ जो एक-3 के अन्तर्गत नियाल संबंधी
मार्गदर्शी सिद्धांत जिन देशों में इस प्रकार के नियाल को मात्रा-
प्रतिक्रियों के सहत कवर किया जाता है।

सं. 1/110/91-ई पी (टी एण्ड जे)-1 (अपरेल) :- उपरोक्त
विषय पर दिनांक 31-8-90 की अधिसूचना सं. 1/4/90-ई. पी.
(टी एण्ड जे)-1 (अपरेल) और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. 1/99/90
ई पी (टी एण्ड जे) 1 (अपरेल) दिनांक 7-8-91, इ 1/4/90-ई. पी.
(टी एण्ड जे) 1 दिनांक 13-11-91 तथा 1/4/90-ई. पी. (टी एण्ड जे)-
1 (अपरेल) दिनांक 11-12-1991 की ओर द्यान आकर्ति किया जाता
है। यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 31-8-1990 की अधिसूचना
सं. 1/4/90-ई. पी. (टी एण्ड जे) (अपरेल) में निम्नोक्त अनुसार संशोधन
किया जाए :

2. पैरा 16 में एक नया उप-पैरा (iv) जैसा दिया जाएगा जो इस
प्रकार पढ़ा जाए :

16 (iv) (क) उन नियालों को जिनको आधार प्रवाहि के बीच
उनके नियाल नियालन के घावार पर संबंधित अवैदन
वर्ष के लिये 25,000 प्रश्न में अवधित विना नियालन
हकदारी का आवैदन किया गया हो। जिनमें सभी देशों/
श्रेणियों को नियाल आमिन है ई एम शी/बी जो के स्थान
पर निम्नलिखित शर्तों पर वैध आवासन (एल यू टी)
देने का विकल्प होगा :—

(क) ई एम शी/बी जी के स्थान पर वैध आवासन
देने की सुविधा विना नियालन हकदारी, गैर-
कोटा हकदारी, नियाल नियाल हकदारी और
सार्वजनिक क्षेत्र हकदारी योजनाओं के प्रत्यक्ष
पात्र नियालों की हकदारियों के विस्तार/
पुरा वैवना में लागू होंगी। यह सुविधा
पड़ते आओ, पहले पात्रों योग्या में सार्वतनो
या विस्तार के लिये उपयोग नहीं होगी।
यह सुविधा गैर-कोटा हकदारी योजना अवशा
विना नियालन के अंतर्गत द्वारा प्राप्त हकदारियों
के विस्तार/पुरा वैवना में भी लागू नहीं होगी।

(ख) यदि वैध आवासन में शामिल की गई हकदारियों
के संबंध में जात की गई किसी धनराशि के

लिये निर्यात हकदारी विनरण नोति के अनुसार
महानिदेशक, अपैरल निर्यात सवधंत
परिषद् दावा करता है तो सबधित निर्यातक
को जिसने ऐसा आश्वासन दिया है, महानि-
देशक, अपैरल निर्यात सवधंत परिषद् द्वारा किए
गए ऐसे दावे की तिथि से 90 दिनों की अवधि
के भीतर दावा की गई ऐसी राशियों का भुगतान
करना होगा। यदि ऐसा करने में वह असफल
होता है तो निर्यातक लदान का किसी भी प्रकार
दा प्रभावीरण न तरने, कि तो भी योजना में
दृष्टान्त न के तरफ़ प्रभाव द्वयका इ प्रम डी/
दो शेर्कर के रुदा निये गये दूर ने

(7) यहाँ प्रिया ने रोका है कि वह उस जीवों का दाता नहीं है जो उसके लिए उत्तम विकास के लिए उनकी सहायता करते हैं। इसका अर्थ यह है कि उसकी सुविधा का लाभ उसके लिए उत्तम है जो उसके लिए उत्तम है।

(घ) इसमें भी/भी जी पर नाम हानि का न मार्गदर्शी सिद्धन्त -था शर्ते आवश्यक परिवर्तन सहित वैध आवधारन पर भी लागू होते ।

3. मोजूदा पंरा 16 (iv) से 16 (vii) की स्थिति में परिवर्तन करके 16 (v) से 16 (viii) कर दिया जाएगा।

4. समय-समय पर संशोधित दिनांक 31-8-90 की अधिसूचना सं.
 1/4/90-ई पी (टी एड जे) -1 (अपैरल) की अन्य सभी शर्तें यथावत
 बदली रखेगी।

एस नारायणन, संयक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 1992

Subject : Guidelines for Export Under OGL-3 in respect of garments and knitwear to countries where such exports are covered under quantitative restraints for the calendar years 1991-93

No. 1|110|91-EP(T&J)-I (Apparel).—Attention is invited to Notification No. 1|4|90-EP(T&J)-I (Apparel) dated 31-8-90 on the above mentioned subject and subsequently amended vide Notification No. 1|9|90-EP(T&J)-I (Apparel) dated 7th August 91; 1|4|90-EP(T&J)-I dated 13th November 1991 and 1|4|90-EP(T&J)-I (Apparel) dated 11-12-1991. It has

been decided to amend the Notification No. 14/90-EP (T&J)I (Apparels) dated 31-8-90 as follows :

2. In Para 16, a new sub-para (iv) shall be inserted which reads :

'16 IV. Exporters who have been allotted Past Performance Entitlements of not less than 25,000 pcs. for the respective allotment year on the basis of their export performance during the base period, for all country categories taken together, will have an option of submitting a Legal Undertaking (LUU) in place of FMT 'BG, subject to the following conditions:-

- (c) The facility of submitting LUT in place of EMD|BG will apply to extension/re-validation of the entitlements of eligible exporters in FPI, NQE, MEE and PSM systems. In FCFS system, this facility will not be available either for allotments or for extension. The facility will also not apply to extension/re-validation of entitlements obtained by transfer in Past Performance or Non-Quota Entitlement systems.
 - (b) If DG, AEPC raises a claim, in terms of the Export Entitlement Distribution Policy, for any forfeiture amounts in respect of entitlements covered by a Legal Undertaking, the exporter/concern which had submitted the Legal Undertaking would remit the amounts so claimed by DG, AEPC within a period of 90 days from the date of such claim, failing which the exporter will not be eligible to apply for or obtain any certification of shipping bills, transfer of entitlements or return of EMD|BGS in any systems until the amounts are remitted and DG, AEPC decides to re-instate these facilities for the exporter.
 - (c) DG, AEPC may withdraw the facility of submitting LUT in place of EMD|BG for any exporters who are otherwise eligible for the facility, but have failed to remit any forfeiture amounts within the stipulated period of 90 days
 - (d) The guidelines and stipulations applicable to EMD|BG will also apply to LUT, mutatis mutandis

3. The existing paras 16 (iv) to 16 (vii) shall be renumbered to 16 (v) to 16 (viii).

4. All other terms and conditions of Notification No. 1[4]90-EP(T&J)-I (Apparels) dated 31.8.90 amended from time to time remain unchanged.

S. NARAYANAN, Lt. Secy.